

Separation of powers

Worked institutional practice

English Part 1 Hindi on page 2

Worked institutional dilemma

Hypothetical facts: Parliament has enacted a fictional Water Access Support Act. For this exercise, assume it authorises the ministry to allocate repair grants using published need criteria. The ministry instead issues a circular giving priority to constituencies represented by the governing party. Residents point to the circular's departure from the assumed Act. The minister replies that an elected government's choice cannot be questioned. Some MPs propose questioning the ministry. An activist asks a court to choose every repair project itself. No court has decided this fictional dispute.

Your task: recommend an institutional response. Distinguish checking a decision from replacing the decision-maker. Do not invent an actual judgment, a real statute or a guaranteed remedy.

Compare the options and their limits

Option A: leave everything to the ministry because it is part of an elected government. This recognises an executive role but fails to answer the residents' specific legal objection. Electoral support does not, by itself, show that the circular fits the stipulated Act. Ask for the criteria, circular and reasons.

Option B: ask the court to run the whole grants programme. This responds to possible unfairness but jumps from identifying a defect to taking over every allocation. The facts have not established why such a sweeping remedy is necessary or legally available. A preferred alternative policy is not itself a legal test.

Option C: combine legislative scrutiny with a focused legal challenge. MPs can question the ministry's reasons; residents can seek appropriate legal scrutiny of the specific departure alleged. Those processes answer different questions. The ministry should examine and correct any departure within its lawful authority. A court's jurisdiction, findings and suitable relief still have to be established.

Recommended reasoning: C best fits the stated problem because it keeps accountability and institutional limits together. It is not a prediction that a petition will succeed. Verify the actual law, evidence and available forum in any real dispute.

शक्तियों का पृथक्करण

हल सहित संस्थागत अभ्यास

हिंदी भाग 1 अंग्रेजी रूप पृष्ठ 1 पर

संस्थागत दुविधा का हल सहित उदाहरण

काल्पनिक तथ्य: संसद ने एक काल्पनिक जल उपलब्धता सहायता अधिनियम बनाया है। इस अभ्यास में मानें कि वह मंत्रालय को जरूरत के प्रकाशित मानदंडों के आधार पर मरम्मत अनुदान आवंटित करने का अधिकार देता है। मंत्रालय इसके बजाय सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने वाला परिपत्र जारी करता है। निवासी बताते हैं कि परिपत्र इस काल्पनिक अधिनियम से हटता है। मंत्री कहते हैं कि निर्वाचित सरकार की पसंद पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। कुछ सांसद मंत्रालय से प्रश्न पूछने का प्रस्ताव रखते हैं। एक कार्यकर्ता अदालत से प्रत्येक मरम्मत परियोजना स्वयं चुनने को कहता है। किसी अदालत ने इस काल्पनिक विवाद का निर्णय नहीं किया है।

आपका काम: संस्थागत प्रतिक्रिया सुझाएँ। निर्णय की जाँच और निर्णयकर्ता का स्थान लेने में अंतर करें। कोई वास्तविक फैसला, वास्तविक कानून या निश्चित उपचार न गढ़ें।

विकल्पों और उनकी सीमाओं की तुलना

विकल्प A: मंत्रालय निर्वाचित सरकार का भाग है, इसलिए सब कुछ उसी पर छोड़ दें। इसमें कार्यपालिका की भूमिका पहचानी गई है, लेकिन निवासियों की विशिष्ट कानूनी आपत्ति का उत्तर नहीं मिलता। चुनावी समर्थन से अपने-आप यह सिद्ध नहीं होता कि परिपत्र अभ्यास में माने गए अधिनियम के अनुरूप है। मानदंड, परिपत्र और कारण माँगें।

विकल्प B: अदालत से पूरी अनुदान योजना चलाने को कहें। इसमें संभावित अन्याय की चिंता है, लेकिन किसी दोष की पहचान से सीधे प्रत्येक आवंटन अपने हाथ में लेने तक छलाँग लगती है। दिए गए तथ्यों से यह स्थापित नहीं हुआ कि इतना व्यापक उपचार आवश्यक या कानूनी रूप से उपलब्ध क्यों है। पसंद की दूसरी नीति अपने-आप कानूनी कसौटी नहीं बन जाती।

विकल्प C: विधायी जाँच के साथ केंद्रित कानूनी चुनौती रखें। सांसद मंत्रालय से उसके कारण पूछ सकते हैं; निवासी बताए गए विशिष्ट विचलन की उचित कानूनी जाँच चाह सकते हैं। ये प्रक्रियाएँ अलग प्रश्नों का उत्तर देती हैं। मंत्रालय को अपने वैध अधिकार के भीतर किसी विचलन की जाँच और सुधार करना चाहिए। अदालत की अधिकारिता, निष्कर्ष और उपयुक्त राहत को फिर भी स्थापित करना होगा।

सुझाए गए तर्क का आधार: C दी गई समस्या के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि उसमें जवाबदेही और संस्थागत सीमाएँ साथ रहती हैं। यह याचिका की सफलता की भविष्यवाणी नहीं है। वास्तविक विवाद में वास्तविक कानून, साक्ष्य और उपलब्ध मंच की पुष्टि करें।

A worked answer and its reasoning

English Part 2 Hindi on page 4

A worked answer

Functional separation requires each institution to perform its task while remaining answerable for its use of power. In the hypothetical grant dispute, the central issue is whether the ministry's circular respects the authority and criteria assumed in the Act, not which institution is politically more important.

The ministry should explain its selection rule and examine the claimed departure from the Act. MPs questioning that explanation exercise legislative scrutiny; asking for reasons need not mean administering each project themselves. The residents' legal objection is also distinct from a request to replace the government's entire policy with their preferred programme.

A focused challenge would identify the relevant rule, the circular and the alleged inconsistency, then seek relief appropriate to any defect established before a competent court. The minister's claim of complete immunity is too broad. Equally, asking the court to select every project skips questions about jurisdiction, evidence and the necessity of that remedy. The hypothetical facts do not determine a real judicial outcome.

The sound response therefore combines explanation and correction by the executive, scrutiny by the legislature and legally bounded adjudication. Accountability is weakened both when an institution refuses every check and when checking becomes an unexplained takeover of another institution's work. The answer should defend scrutiny while stating its purpose and limits.

Why the answer works

Paragraph 1 defines the issue: it turns a slogan about supremacy into a question about an identified action.

Paragraph 2 allocates tasks: explanation, political scrutiny and a legal objection are separated without assuming only one can operate.

Paragraph 3 bounds the remedy: it rejects both blanket immunity and an automatic judicial takeover, and preserves uncertainty about the outcome.

Paragraph 4 answers the question: it gives a reasoned recommendation rather than ending with an unrelated list of cases.

नमूना उत्तर और उसका तर्क

हिंदी भाग 2 अंग्रेजी रूप पृष्ठ 3 पर

एक नमूना उत्तर

कार्यात्मक पृथक्करण में प्रत्येक संस्था अपना काम करती है और शक्ति के उपयोग के लिए जवाबदेह रहती है। काल्पनिक अनुदान विवाद में मुख्य प्रश्न यह है कि मंत्रालय का परिपत्र अधिनियम में माने गए अधिकार और मानदंडों के अनुरूप है या नहीं; यह नहीं कि कौन-सी संस्था राजनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है।

मंत्रालय को अपना चयन-नियम समझाना चाहिए और अधिनियम से कथित विचलन की जाँच करनी चाहिए। उस स्पष्टीकरण पर सांसदों के प्रश्न विधायी जाँच हैं; कारण पूछने का अर्थ प्रत्येक परियोजना का प्रशासन स्वयं करना आवश्यक नहीं है। निवासियों की कानूनी आपत्ति भी पूरी सरकारी नीति को उनकी पसंद की योजना से बदलने की माँग से अलग है।

केंद्रित चुनौती में संबंधित नियम, परिपत्र और कथित असंगति बताकर सक्षम अदालत के समक्ष सिद्ध होने वाले दोष के अनुरूप राहत माँगी जाएगी। मंत्री का पूर्ण छूट का दावा बहुत व्यापक है। इसी तरह, अदालत से प्रत्येक परियोजना चुनने को कहना अधिकारिता, साक्ष्य और उस उपचार की आवश्यकता से जुड़े प्रश्नों को छोड़ देता है। काल्पनिक तथ्य किसी वास्तविक न्यायिक परिणाम को निश्चित नहीं करते।

इसलिए उचित प्रतिक्रिया में कार्यपालिका का स्पष्टीकरण और सुधार, विधायिका की जाँच तथा कानूनी सीमाओं के भीतर न्यायनिर्णयन साथ आते हैं। जवाबदेही तब भी कमजोर होती है जब कोई संस्था हर जाँच को नकार दे, और तब भी जब जाँच बिना पर्याप्त कारण दूसरी संस्था का काम अपने हाथ में लेना बन जाए। उत्तर में जाँच का समर्थन करते हुए उसका उद्देश्य और सीमाएँ स्पष्ट करनी चाहिए।

यह उत्तर प्रभावी क्यों है

अनुच्छेद 1 मुद्दा तय करता है: सर्वोच्चता के नारे को एक पहचानी गई कार्रवाई के प्रश्न में बदलता है।

अनुच्छेद 2 काम बाँटता है: स्पष्टीकरण, राजनीतिक जाँच और कानूनी आपत्ति को अलग करता है, पर यह नहीं मानता कि केवल एक प्रक्रिया ही चल सकती है।

अनुच्छेद 3 उपचार की सीमा बताता है: पूर्ण छूट और अदालत के स्वतः सब काम संभालने, दोनों को नकारता है तथा परिणाम की अनिश्चितता बनाए रखता है।

अनुच्छेद 4 प्रश्न का उत्तर देता है: असंबद्ध मुकदमों की सूची पर समाप्त होने के बजाय कारण सहित सुझाव देता है।

Precise qualifications and solved practice

English Part 3 Hindi on page 6

Keep the institutional limits precise

Article 121 (Parliament): discussion of the conduct of a Supreme Court or High Court judge in the discharge of duties is barred, except on a motion to present an address to the President seeking the judge's removal.

Article 211 (State legislatures): discussion of such judicial conduct is barred; this Article contains no corresponding removal-motion exception.

Articles 122(1) and 212(1): parliamentary and State-legislature proceedings, respectively, cannot be challenged merely for an alleged irregularity of procedure. This is not blanket immunity from judicial review for substantive illegality or unconstitutionality.

Worked contrast: A complaint alleges only a breach of an internal debate-timing rule: a mere procedural irregularity is protected. A complaint instead identifies a violation of a constitutional requirement: Articles 122(1) and 212(1) do not automatically bar judicial scrutiny. The distinction is the ground of challenge, not whether the court agrees with a political decision.

Do not skip the next question: an allegation of unconstitutionality is not proof of it. Identify the requirement, the alleged breach and the available legal route before predicting a result.

Solved transfer exercises

1. A minister says: "Our policy is popular, so its legality does not need explanation." What is missing?

Solution: Popularity and legal authority answer different questions. Ask which power supports the action and how it fits the applicable rule. Do not infer illegality merely from criticism either; the rule and facts still need checking.

2. Two challenges concern parliamentary proceedings. One alleges only that an internal speaking-time rule was breached; the other identifies a constitutional requirement allegedly violated. Must both receive the same answer?

Solution: No. The first concerns the procedural-irregularity protection described above. The second is not automatically barred by Article 122(1), but naming a constitutional ground does not prove a breach or guarantee relief. Apply the analogous distinction under Article 212(1) for a State legislature.

3. A learner transfers Article 121's removal-motion exception to a State legislative debate about a High Court judge's conduct in judicial duties. Correct the reasoning.

Solution: The learner has carried an exception from one Article into another. Article 211 contains no corresponding exception. Identify the institution and the relevant Article first; disagreement with a judgment does not establish permission for the proposed conduct debate.

सटीक सीमाएँ और हल सहित अभ्यास

हिंदी भाग 3 अंग्रेजी रूप पृष्ठ 5 पर

संस्थागत सीमाएँ ठीक समझें

अनुच्छेद 121 (संसद): सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य-निर्वहन संबंधी आचरण पर चर्चा वर्जित है। अपवाद है न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति से प्रार्थना करने वाला समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव।

अनुच्छेद 211 (राज्य विधानमंडल): न्यायाधीश के ऐसे आचरण पर चर्चा वर्जित है; इस अनुच्छेद में हटाने के प्रस्ताव वाला समान अपवाद नहीं है।

अनुच्छेद 122(1) और 212(1): क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को केवल प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यह मूलभूत अवैधता या असंवैधानिकता के मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन से पूर्ण छूट नहीं है।

समझा हुआ उदाहरण: एक शिकायत केवल बहस के समय संबंधी आंतरिक नियम के उल्लंघन की है: महज़ प्रक्रियागत अनियमितता को संरक्षण मिलता है। दूसरी शिकायत किसी संवैधानिक आवश्यकता के उल्लंघन की है: अनुच्छेद 122(1) और 212(1) न्यायिक जाँच पर अपने-आप रोक नहीं लगाते। अंतर चुनौती के आधार में है, किसी राजनीतिक निर्णय से अदालत की सहमति या असहमति में नहीं।

अगला प्रश्न न छोड़ें: असंवैधानिकता का आरोप उसका प्रमाण नहीं है। परिणाम बताने से पहले संबंधित आवश्यकता, कथित उल्लंघन और उपलब्ध कानूनी मार्ग की पहचान करें।

नए प्रसंगों में प्रयोग के हल सहित अभ्यास

1. एक मंत्री कहते हैं: “हमारी नीति लोकप्रिय है, इसलिए उसकी वैधता समझाने की जरूरत नहीं।” तर्क में क्या कमी है?

हल: लोकप्रियता और कानूनी अधिकार अलग प्रश्नों के उत्तर हैं। पूछें कि कार्रवाई किस शक्ति पर आधारित है और लागू नियम के अनुरूप कैसे है। केवल आलोचना से अवैधता भी न मान लें; नियम और तथ्यों की जाँच फिर भी आवश्यक है।

2. संसदीय कार्यवाही की दो चुनौतियाँ हैं। पहली में केवल बोलने के समय के आंतरिक नियम का उल्लंघन बताया गया है; दूसरी में कथित रूप से टूटी संवैधानिक आवश्यकता पहचानी गई है। क्या दोनों का उत्तर समान होगा?

हल: नहीं। पहली ऊपर बताए प्रक्रियागत अनियमितता के संरक्षण से जुड़ी है। दूसरी पर अनुच्छेद 122(1) अपने-आप रोक नहीं लगाता, लेकिन संवैधानिक आधार बताने से उल्लंघन सिद्ध या राहत निश्चित नहीं होती। राज्य विधानमंडल के लिए अनुच्छेद 212(1) के अंतर्गत समान भेद लागू करें।

3. एक विद्यार्थी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायिक कर्तव्य-निर्वहन संबंधी आचरण पर राज्य विधानमंडल की बहस में अनुच्छेद 121 का हटाने के प्रस्ताव वाला अपवाद लागू कर देता है। तर्क सुधारें।

हल: विद्यार्थी ने एक अनुच्छेद का अपवाद दूसरे में पहुँचा दिया है। अनुच्छेद 211 में वैसा अपवाद नहीं है। पहले संस्था और संबंधित अनुच्छेद पहचानें; किसी फैसले से असहमति प्रस्तावित आचरण-चर्चा की अनुमति सिद्ध नहीं करती।

Apply the method and test the analogy

English Part 4 Hindi on page 8

Solved transfer exercises continued

4. Revise this conclusion: "Judicial review means judges should run every grant programme whenever citizens object."

Solution: Better: "A specific legal objection should be examined through an available legal route, with relief tied to any defect established. An objection alone does not justify transferring the entire programme to the court." This revision states the ground, route and limit instead of assuming a result.

5. Transfer the method. In a fictional hospital-supply scheme, assume the governing rule requires supplies to be allocated among hospitals according to need. Officials instead favour hospitals whose managers have personal contacts with them. A legislator asks for records; a hospital representative demands that the court decide every future allocation. Give a bounded response.

Solution: First compare the records and reasons with the stipulated rule. Seeking an explanation supports accountability; any legal challenge should identify the alleged departure. Do not endorse contacts as a substitute for the assumed criterion, or promise that a court will decide every future allocation. The appropriate forum and remedy require actual law and evidence.

A bounded cricket and DRS analogy

Use cricket only as a memory aid. In a simplified picture, rule-making, playing and adjudicating are different jobs. This helps explain why the person taking an action should not also have unchecked power to settle every objection to it.

Where DRS helps: it suggests the idea of a defined review process rather than a player changing a decision by insisting on it. **Where it stops:** DRS is not an executive veto over courts, an appeal route for every constitutional dispute or a model of how Indian institutions are appointed and held accountable. Constitutional institutions also have overlaps that the picture leaves out.

Test the analogy: "The minister is a player, so the minister can reverse the court's decision through DRS." This inference fails. A sporting comparison supplies no legal power; the actual constitutional or legal route must be identified.

तरीका लागू करें और उपमा परखें

हिंदी भाग 4 अंग्रेज़ी रूप पृष्ठ 7 पर

हल सहित अभ्यास आगे

4. यह निष्कर्ष सुधारें: “न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि नागरिक आपत्ति करें तो न्यायाधीश हर अनुदान योजना चलाएँ।”

हल: बेहतर रूप: “विशिष्ट कानूनी आपत्ति की जाँच उपलब्ध कानूनी मार्ग से होनी चाहिए और राहत सिद्ध दोष से जुड़ी होनी चाहिए। केवल आपत्ति पूरी योजना अदालत को सौंपने का औचित्य नहीं है।” यह संशोधन परिणाम मान लेने के बजाय आधार, मार्ग और सीमा बताता है।

5. तरीके को नए प्रसंग में लागू करें। काल्पनिक अस्पताल-आपूर्ति योजना में मानें कि लागू नियम के अनुसार अस्पतालों को जरूरत के आधार पर सामग्री आवंटित की जानी चाहिए। अधिकारी इसके बजाय उन अस्पतालों को प्राथमिकता देते हैं जिनके प्रबंधकों से उनके निजी संपर्क हैं। एक विधायक अभिलेख माँगता है; एक अस्पताल का प्रतिनिधि अदालत से हर भावी आवंटन तय करने को कहता है। सीमाओं सहित प्रतिक्रिया दें।

हल: पहले अभिलेखों और कारणों की तुलना अभ्यास में माने गए नियम से करें। स्पष्टीकरण माँगना जवाबदेही का समर्थन करता है; कानूनी चुनौती में कथित विचलन पहचाना जाना चाहिए। निजी संपर्कों को माने गए मानदंड का विकल्प न मानें और अदालत द्वारा हर भावी आवंटन तय करने का वादा न करें। उचित मंच और उपचार तय करने के लिए वास्तविक कानून तथा साक्ष्य चाहिए।

सीमाओं सहित क्रिकेट और DRS की उपमा

क्रिकेट को केवल याद रखने की उपमा बनाएँ। एक सरल चित्र में नियम बनाना, खेलना और निर्णय देना अलग काम हैं। इससे समझ आता है कि कार्रवाई करने वाले व्यक्ति को उस पर उठने वाली हर आपत्ति का निर्णय करने की अनियंत्रित शक्ति भी क्यों न मिले।

DRS कहाँ उपयोगी है: वह एक निर्धारित समीक्षा-प्रक्रिया का विचार देता है, खिलाड़ी के केवल आग्रह से फैसला बदलने का नहीं।

उपमा कहाँ समाप्त होती है: DRS अदालतों पर कार्यपालिका का वीटो, हर संवैधानिक विवाद का अपील-मार्ग या भारतीय संस्थाओं की नियुक्ति और जवाबदेही का नमूना नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं की भूमिकाएँ कुछ क्षेत्रों में जुड़ती भी हैं, जिसे यह चित्र नहीं दिखाता।

उपमा की परीक्षा: “मंत्री खिलाड़ी हैं, इसलिए DRS के जरिए अदालत का फैसला पलट सकते हैं।” यह निष्कर्ष गलत है। खेल की तुलना कोई कानूनी शक्ति नहीं देती; वास्तविक संवैधानिक या कानूनी मार्ग पहचानना होगा।